MR. CHAIRMAN: Now the last question. Yes, Mr. Mody.

SHRI PILOO MODY; But the last question is the first question on this.

MR. CHAIRMAN: No; last in the series.

SHRI PILOO MODY: Sir, this question makes a charge and the Minister has accepted the charge. He also says that for 20 years they have not been able to collect. Now he has to spend another 20 years trying to do it.

MR. CHAIRMAN: But he was not there for these 20 years.

SHRI PILOO MODY; But I am talking about the Ministry. The Minister is only a spokesman for the Ministry.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI PILOO MODY: Therefore, Sir, it is redundant really to pursue this question and you have rightly said that this should be the last question. I say this because in part (b) of his reply he says: "The information i_s being collected from the Zona] Railways and will be laid on the Table of the House." Now, when he is going to collect this information which is 20 years old, it is going to take more time for him to get the answer. Therefore, may I suggest that we will take up this question later on after the information is collected? And. Sir, I would also like the Minister to remember at that time that certain things become time-barred after a period of time and therefore, what has become time-barred and that he has not been able to collect, he need not spend the bureaucracy's time on it and also to pursue what he cannot get by law. Therefore, he may spend the time on what is not time-barred and present us with a comprehensive list of what is collectable.

SHRI MALLIKARJUN: I have taken a serious view of this question and I have also instructed the concerned authorities to furnish the details and take early action to recover the dues.

MR. CHAIRMAN: Question No. 187.

Robbery incidents in trains

*187. SHRI SADASIV BAGAIT-KAR:

SHRI LADLI MOHAN NIGAM; SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was an attempt recently to rob train passengers by stopping the train in Bombay in broad day light;

(b) whether it is a fact there has been a country-wide increase in incidents of robbing of train passengers and criminal gangs are emboldened to operate even in suburb of Bombay;

(c) whether it is also a fact that railway staff posted in Bombay feel terrorised by the operation of these gangs; and

(d) if so, what action Government have taken to remedy the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (d) A~ statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No, Sir.

(b) It is not a fact that cases of robberies in trains have shown an increase over the Indian Railways. However, an increasing trend of robberies in trains is noticeable in the suburban area of Bombay.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri B. Satyanarayan Reddy.

(c) No, Sir. --------

(d) The following steps are being taken to remedy the situation:

(1) Special Squads are earmarked for carrying out raids and for travelling in local trains as preventive measure. They have been directed particularly, to look after the security of lady commuters.

(2) Known criminals and suspects • are being apprehended and prosecuted.

(3) Armed escorting in local trains particularly which run around mid-night is being done.

(4) Particular watch is being kept on areas which are prone to crimes.

(5) Nakabandi is being done. Re-suits achieved are quite encouraging. Government Railway Police was able to arrest during such Nakabandi criminals who were found carrying lethal weapons. This Nakabandi was introduced recently- .

(6) Railway Protection Force is deployed to assist Police in escorting, Nakabandi and conducting raids etc.

(7) Railways maintain close liaison with State Police authorities at all lavels for ensuring safety of passengers traveling in trains. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY; Sir, every day such incidents are taking place throughout the country. (Every time the Government comes and gives one explanation or the other. But at no time has it taken a serioug note of these incidents. I would like to know, in recent times, what are the steps the Government has taken to prevent these incidents?

SHRI MALLIKARJUN: Sir, such things are incidental. Here the incident was published in the *Times* of *India* on 23-4-80 in Bombay. A student had gone and complained. Some youth was standing there. The other person who lost their belong-ings die" not complain to the police. Only because of the appearance of newspaper report it has come to light. For such incidents we cannot exactly evolve any measures to face them.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: The complaint had been made by the sufferer who had been robbed. Properties were not traced out.

SHRI MALLIKARJUN: I have clearly mentioned that the complaint was made by a student. What happened, Sir, exactly, when the train started from the platform, some youth were standing there and from the first-class passenger compartment they dragged something which was in their hands. One student was with his books in that compartment. ' His bag was torn but the books were saved. The student alleged a complaint at the Dadar Station. In this matter, investigations were conducted but actually nothing has been found. The Railways could do nothing about it.

श्री श्याम लाल यादव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं उन्होंने जैसे अपने बयान में कहा है कि गाड़ियों में लूट की घटनाएं बढ़ने की टेंडेंसी है, ऐसा दिखाई देता है और उन्होंने जो सुझाव दिया है और जो कदम उठाए हैं, उनका वर्णन किया है । मैं उसमें एक ही बात जानना चाहता हूं कि जो व्य स्था सुरक्षा कर्मचारी चलती गाड़ियों में रहते हैं, क्या मंत्री महोदय जी की नजर में यह बात नहीं आई कि यह सुरक्षा कर्म-चारी आज तक जितनी डकैतियां रेलों में पड़ी हैं, किसी व्यक्ति को चलती हुई ट्रेन में नहीं पकड़ पाए ? जब डकैतियां पड़ती हैं तो वे कहीं न कहीं दूसरी जगह दिखाए जाते हैं बाद में गिरफ्तारियां होती हैं, एन्कवायरी होती है । लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे कि जब किसी ट्रेन में लूट पड़े, रावरी पड़े और सुरक्षा कर्मचारी उस ट्रेन में चल रहे हों और वे

किसी को नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : हुजूर, इसमें हमारी कुछ दिक्कतें हैं और मैं उन्हें सदन के सम्मुख नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं । हम लोगों के नोटिस में कई केसेज आए हैं कि ट्रेन्स में डकैतियां पड़ी हैं । चार पांच महीनों में बढ़ी हैं, पहले भी बढ़ी हैं यह गम्भीर चिन्ता का विषय है । श्रीमन, आर० पी० एफ० को पुलिस की कोई पावर्स नहीं हैं । यह एक वाच एण्ड वार्ड की तरह से है । अगर किसी जगह डकैती वगैरह पड़ जाती है तो जी० आर० पी० को रिपोर्ट करनी पड़ती है और जी० आर० पी० स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती है ।

श्री सभापति : सवाल यह है कि वक्ती गिरफ्तारी क्यों नहीं होती ? उसका क्या इंतिजाम हो सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : श्रीमन, मैं बता रहा हूं । जी० आर० पी० को हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है । अब हमने अपने सुरक्षा अधिकारी भेजने का काम शुरु किया है । पहले इसका कोई इंतिजाम नहीं था । कुछ थोड़े बहुत जाते थे तो किसी एक कंपार्टमेंट में बैठे और दूसरे कंपार्टमेंट में डाका पड़ गया तो स्टेशन पर गाड़ी जब आयेगी तब रिपोर्ट की जाती, तब तक वह लूट-मार कर चले जाते हैं । अब हमने स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत की है और यह तय हुआ है कि जी० आर० पी० की संख्या बढ़ाई जाए । उन्होंने इसको मंजूर किया है और इस दल पर जो खर्च होगा वह पचास-पचास प्रतिशत हम बाटेंगे इस पर मंजूरी हो गई है । अब जी० आर० पी० की संख्या बढ़ाई जा रही है । हमने एक ऐंटी डकैती स्क्वाड भी बनाया है जो चलती गाड़ियों में रहेगा । खासकर जिन डिब्बों में डकैती पड़ने का डर होता है वे वही डिब्बे होते हैं जिनमें यात्रियों की संख्या कम होती है । उनमें जरूर रखे जायेंगे । अब ऐसी डकैतियां पिछले कुछ दिनों से जब से इंतिजाम हुआ है तब से लगता है कि डकैतियों की संख्या कम हुई है ।

श्री सभापति : जी० आर० पी० को जब रिपोर्ट होती है तो उसमें वक्त बहुत ज्यादा सर्फ होता है और बाद में तफ्तीश जब शुरु होती है तो पकड़ में नहीं आता, यह सवाल यादव जी का था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, मैं शिकायत नहीं करना चाहता और यह मुनासिब भी नहीं होगा, लेकिन यह मानना पड़ता है कि जी० आर० पी० बड़ी इन-एफेक्टिव रही है । कभी उसने इस दिशा में उचित कार्यवाही नहीं की है । रिपोर्ट भी की गई तो कोई ज्यादा कार्यवाही नहीं की । स्टेट गवर्नमेंट से हमने बातचीत की और स्टेट गवर्नमेंट से हमको ऐश्योरेंस मिला है कि वे इस ओर ज्यादा कार्य करेंगे । उन्होंने हमसे कोआपरेट करने का वायदा किया है और एक समझौता भी उनसे हुआ है कि जी० आर० पी० की तादाद बढ़ा दें । मान्यवर, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन यह भी मैं कह सकता हूं कि मुझे स्टेट्स का जो अनुभव है उससे मालूम है कि जी० आर० पी० में भी वही आदमी जाते हैं जो पुलिस फोर्स में निकम्मे रहे हों । उनको जी० आर० पी० में भेजा जाता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन, एक फैक्टर इसमें इंपोर्टेंट है । जब डकैती पड़ती है तो जो पैसेंजर्स लूटे जाते हैं उनके सहयोगी पैसेंजर्स डर के मारे इंटरफियर नहीं करते हैं या रेलवे कर्मचारी भी हिम्मत नहीं करते हैं । चूंकि डाकू आर्म्ड होते हैं, पिस्तौल वाले होते हैं, क्या मंत्री इस पर विचार करेंगे कि जो

लोग, चाहे मुसाफिर हों या रेल कर्मचारी डाकुओं के द्वारा डकैती के वक्त जान से मारे जायें या टोटली डिसेबल हो जायें उनको कंपेंसेशन देंगे ताकि जो कुलीग पेसैंजर्स हैं या रेलवे कर्मचारी हैं ऐसे मौकों पर वह हिम्मत कर सकें। डाकुओं को पकड़ने में या उनका मुकाबला करने में मदद कर सकें, इसके लिए कोई इंसेंटिव देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, यह सुझाव है, इस पर विचार करेंगे।

श्री रामेश्वर सिंह : मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है सदन के सामने कि हमारी जी० आर० पी० और रेलवे सुरक्षा दल दोनों निकम्मे साबित हुए हैं और उसकी वजह से हम इसकी रोकथाम करने में असमर्थ हैं। तो क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि 30 वर्षों से लगातार आपने जब कंट्रोल नहीं किया जी० आर० पी० और रेलवे सुरक्षा दल को, उनको सुरक्षित नहीं किया, सुसज्जित नहीं किया, उनमें लोगों के जान माल की हिफाजत करने की क्षमता नहीं होती, तो क्या इस बात की सदन को आप गारन्टी देंगे कि भविष्य में, इस तरह की वारदातें नहीं होंगी और पुलिस और जी०आर०पी० को आप सक्षम बनायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : जी०आर०पी० को हम सक्षम बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स इस मामले में हमारा साथ दे रही हैं। हम उनको सक्षम बना रहे हैं। आर०पी०एफ० को पुलिस की पावर दी जाए, यह मामला भी हमारे विचाराधीन है। आर०पी०एफ० को पुलिस की पावर्स नहीं हैं। लोगों को गिरफ्तार करने की चालान करने की और बयान लिखने की उनको इजाजत दी जाए। हम यही चाहते हैं कि पुलिस पावर्स उनको दे दी जाए।

श्री सभापति : रेगुलर पुलिस पावर दी जाए।

श्री कमलापति त्रिपाठी : इस पर हम विचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा तो मामला सदन के सम्मुख आएगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। मान्यवर, यह कोई आश्वासन देना कि ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती यह हमारे बूते के बाहर है। हम तो इतना ही आश्वासन दे सकते हैं कि हम पूरी ताकत लगायेंगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये और इसमें रामेश्वर सिंह जी की मदद भी चाहेंगे।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Chairman, Sir, the Minister has just now said that the RPF people are not sufficiently authorised or empowered to arrest. I want to know 'from the Minister one thing. Who pays the salary bill of the RPF people? Whose employees are they? If the Government is spending so much on the salary head of these RPF men, what is the point in not arming them with sufficient powers so that they can stop the incidents and they can arrest on the spot? This is number one. Secondly, Sir, nowadays woman without any companions cannot board the train. Is this the state of affairs that we will have to tolerate in this' country? Is the Government serious about it? If so, what are the stringent measures that the Government want to take to stop all these incidents?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, इसका ताल्लुक तो जनरल ला एंड आर्डर की सिच्युएशन से है। जहां तक आर०पी०एफ० की मामला है यह रेलवे प्रोपर्टी की प्रोटेक्शन के लिये फोर्स बनाई गई है। गोदाम में जो प्रोपर्टी है उसकी चोरी न हो इसकी प्रोटेक्शन के लिये यह फोर्स बनाई गई है। यह सिच्युएशन नई पैदा हो गई है इसलिये हम उनकी मदद ले रहे हैं। इसीलिये हम सोच रहे हैं कि उनको पुलिस पावर दी जाए। जनरल ला एंड आर्डर की सिच्युएशन को देखने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है।

श्री सभापति : रेलवे प्रोपर्टी जो है, the land on which the rail runs, I thought, is vested in the Central Government.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: It i_3 vested in the Central Government.

रेलवे लाइन को भी प्रोटेक्शन होनी चाहिये । रेलवे का जो माल है उसकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिये *(Interruption).* Let me complete. The general la_w and order situation is under the State Government. They should look into it. And unless that improves, 1 think, it will be very-difficult to say anything about it. So far as the Railways are concerned, we ar_e thinking of giving the police powers to the RPF so that they may become effective.

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA: Sir, the hon. Minister has shown some helplessness about the Railway Protection Force that they do not enjoy the powers which are enjoyed by the Government Police. Is he aware that the right of self-defence as regards persons and property is not confined to the person who is attacked or his property being stolen or robbed but also to any other citizen? I can also go 'for the defence of anybody who is attacked in m_v presence or if his property i_g robbed in my presence. You must Ira in the RPF about all these aspects. You do not show helplessness. What you need to do is to train the RPF i_n the rights of self-defence which 3s even projected, as hon Mr. Chairman will confirm, that any person can go to protect the person and property of any of the passengers.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, ओझा जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उन्हें बहुत जानकारी है । जी०आर०पी० की भी जानकारी होगी । मैं भी रह चुका हूं मुझे भी सारी जानकारी है । मैं तो कह रहा हूं कि हमने कोई हेल्पलेसनेस नहीं दिखाई है

(Interruptions)

SHRI PILOO MODY: He asked the question in English.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: Don't try to interrupt me. I am on so that they might become more effective. So far a_a the question ©f self-defence is concerned, that right is there already, jf anybody attacks the RPF personnel, they also try to save themselves.

MR. CHAIRMAN: Very well, we will now go en to the next questkn Quc.'don l\\i 183.

Inventory of goods despatched to Lost Property Offices

•188. SHRI PILOO MODY:†
SHRI R. R. MORARKA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no proper system of keeping inventories of goods despatched to Lost Property Offices either by the despatching station or by the Lost Property Offices, thereby permitting large scale malpractices; and

(b) what type of check is enforced to ensure that the contents of packages are not replaced by fake stuff?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALL1KARJUN): $(_a)$ and (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Rules provide that inventory of all goods transferred to Lost Property Offices should be taken both at the despatching station and in the Lost Property Offices. While inventories are invariably taken at the Lost Property Offices of all goods received, it has not always been possible to take inventory of the contents of each and $ever_v$ package/case at the despatching $statio_n$ before transferring them to

†The question was actually asked on the floor of th_e House by Shri Piloo Mody.